कृषि विकास कोष, रोम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए है। इस मंत्रालय ने इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास सिफारिश की है, कि वह वित्तीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम के साथ मामला उठाए। आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया है कि मामले को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम के साथ उठाया गया है। इस स्तर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि वित्तीय अनुमोदन कब तक दिया जा सकेगा तथा राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी।

मध्य प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

3427. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिये दी गई है, राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की काफी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार आवश्यकतानुसार अधिक व्यावसायिक केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार पिछले वर्ष अनुदान की निर्मुक्ति के मामले में मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करेगी बशर्ते कि उपयोग प्रमाण पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट आदि जैसी विहित शर्तें पूरी की गई हों।

Plight of Senior Citizens

3428. SHRI KRISHAN LAL SHAMRA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that plight of senior citizens of the country is full of misery and despair;

(b) whether Government have taken any census of such persons; and

(c) whether Government have drawn a plan for their welfare by enlarging the scope of social security?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) It cannnot be generalised that the plight of all Senior Citizens of the country is full of misery and despair, it is not unlikely that many of them may not be in a comfortable position both economically and emotionally. The family ties in India are genrally still intact and the welfare of the elderly is taken care of by the family. In the organised sector, the retired persons get pension and other terminal benefits. The State Governments are providing Old Age Pension to the aged people.

(b) The age data of 1991 census is under process. However, as per 1981 census, the number of aged persons of 60 years of age and above was 4.32 crores approximately.

(c) The Government has drawn a scheme of assistance to voluntary organisations for programmes relating to the aged for providing physical, social, emotional, psychological and economic support to the aged (60 years and above) with a view to help them to continue to be usefully active members of the community. Under this scheme, grants-in- aid were released to the voluntary organisations for running 126 Old Age Homes, 182 Day Care Centres and 11 Mobile Medicare Units.

शुष्क शौचालयों का संप्रवाह व्यवस्था में परिवर्तन

3429. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संप्रवाह शौचालय व्यवस्था में परिवर्तित किये गये शुष्क शौचालयों की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के बाद सफाई करने के काम से मुक्त हुए सफाई कामगारों की संख्या कितनी है तथा उन्हें विभिन्न व्यवसायों में पुनर्वासित करने के लिए सफाई कामगारों और उनके परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) अल्प लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत शुष्क शौचालयों को जलवाहित (संप्रवाह) शौचालयों में परिवर्तन की राज्य वार संख्या और इसके द्वारा मुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है (नीचे देखिए) तथा सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अधीन सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न

व्यापारों/व्यवसायों में पुनर्वासित करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कम लागत वाली स्वच्छता योजना

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवर्तित *निर्मित शुष्क शौचालय	मुक्त किए गये सफाई कर्मचारियों की संख्या
1.	आ.प्र.	1,85, 909	2943
2.	अरूणाचल प्रदेश	*शून्य	*शून्य
3.	असम	15,000	416
4.	बिहार	1,86,000	4382
5.	गोवा	*शून्य	*शून्य
6.	गुजरात	सफाई कर्मचारी मुक्त	*शून्य
7.	हरियाणा	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	14,162	432
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-
10.	कर्नाटक	12,293	*शून्य
11.	केरल	11,730	*शून्य
12.	मध्यप्रदेश	4,06,253	605
13.	महाराष्ट्र	1,56,800	3274
14.	मणिपुर	*शून्य	*शून्य
15.	मेघालय	*शून्य	*शून्य
16.	मिजोरम	234	-
17.	नागालैंड	*शून्य	*शून्य
18.	उड़ीसा	45,159	1661
19.	पंजाब	66,072	3300
20.	राजस्थान	1,87,204	1594
21.	सिक्किम	*शून्य	*शून्य
22.	तमिलनाडु	67,751	355
23.	त्रिपुरा	सफाई प्रणाली मुक्त	-
24.	उत्तर प्रदेश	1,47,545	1934
25.	पश्चिम बंगाल	80,700	72
26.	अ. नि. दीव	1,125	50
27.	चंडीगढ	-	-
28.	दादरा नगर हवेली	*शून्य	*शून्य
29.	दमन द्वीव	*शून्य	*शून्य
30.	दिल्ली	8,58,949	-
31.	लक्षद्वीप	*शून्य	*शून्य
32.	पांडिचेरी	1,534	118
	कुल :	24,44,418	21,136

*पद्धति विद्यमान नहीं है।

विवरण- II

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	के दौरान निर्मुक्त धनराशि 1991-92	1992-93	1993-94 (अगस्त, 94 तक)	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	2.55	4.49	-
2.	असम	0.125	2.02	-	-
3.	बिहार	3.50	3.13	-	-
4.	गुजरात	2.50	1.86	2.00	-
5.	हरियाणा	1.50	1.76	7.14	-
6.	जम्मू और कश्मीर	0.025	1.00	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	0.60	2.53	-	-
8.	कर्नाटक	1.75	3.99	-	-
9.	केरल	0.25	0.30	-	-
10.	मध्य प्रदेश	4.00	13.36	12.26	13.80
11.	महाराष्ट्र	3.70	6.59	3.78	-
12.	उड़ीसा	3.50	0.58	1.19	-
13.	पंजाब	3.50	0.58	—	-
14.	राजस्थान	4.75	1.01	2.27	-
15.	तमिलनाडु	5.00	0.80	-	-
16.	उत्तर प्रदेश	8.00	14.94	37.63	-
17.	पश्चिम बंगाल	2.00	3.63	-	-
18.	दिल्ली	3.75	0.05	-	-
19.	पांडिचेरी	0.025	0.05	0	-
20.	नागालैंड	0	-	0.11	-
21.	मेघालय	0.025		-	-
	कुल:	50.50	60.73	70.97	13.80

सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

3430. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सफाई कर्मचारियों के कल्याण हेतु सरकार ने कोई राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा;

(ग) क्या सरकार इसके लिए निर्धारित समयावधि में इस कार्यक्रम को पूर्ण करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या कार्य-योजना बनाई जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नामक